200 टन जन उपयोगी सामग्री पहुंचाई गई है कार्गो विमान से देश के विभिन्न इलाकों में। इसी प्रकार रेलवे ने 8897 रैक्स और 4.57 लाख वैगन से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की है।

सांसदों के भत्तों में से भी हर माह 27 हजार रुपये की कटौती

- निर्वाचन क्षेत्र भत्ते से 21 हजार और स्टेशनरी भत्ते से छह हजार काटे जाएंगे
- सांसदों के वेतन में 30 फीसद कटौती की अधिसूचना जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में धन की कमी ना हो इसके लिए सांसदों के भत्तों में से भी हर महीने 27 हजार रुपये की कटौती की जाएगी। मंगलवार को जारी सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले, सांसदों को मिलने वाले हर महीने एक लाख रुपये के वेतन में से 30 फीसद यानी 30 हजार रुपये कटौती करने की घोषणा की जा चुकी है। मंगलवार रात इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई।

आदेश के मुताबिक सरकार के साथ सलाह-मशविरे के बाद संयुक्त संसदीय समिति ने सांसदों को हर महीने मिलने वाले 70 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में से 30 फीसद कटौती करने की सिफारिश की है। यह रकम 21 हजार रुपये है। सरकार ने कहा है कि एक अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक हर सांसद को अब निर्वाचन भत्ता के रूप में 49 हजार रुपये मिलेंगे।

उल्लेखनीय है कि हर सांसद (लोकसभा और राज्यसभा) को कार्यालय भत्ते के रूप में प्रति माह 60 हजार रुपये मिलते हैं। सरकार की ओर से मिलने वाली इस धनराशि में स्टेशनरी के लिए 20 रुपये शामिल है। मंगलवार रात जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, इसमें से छह हजार रुपये की कटौती की जाएगी और अब हर सांसद को हर महीने स्टेशनरी भत्ता के रूप में 14 हजार रुपये ही मिलेंगे। हालांकि निजी सहायक भत्ता के रूप में मिलने वाले 40 हजार रुपये में से किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।

राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम, वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष व राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला ने इस संबंध में संयुक्त संसदीय समिति की ओर से की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। एक अप्रैल से यह कटौती प्रभावी भी हो जाएगी। सांसद (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2020 के तहत यह कटौती की गई है।

लॉकडाउन से निकलने की योजना के लिए सात दिन अहम : वेंकैया

- कहा- सरकार जो भी फैसला करे, उसका पालन करें

नई दिल्ली, प्रेट्र : उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन का आखिरी हफ्ता इससे बाहर निकलने की रणनीति बनाने के लिए बेहद अहम है क्योंकि सरकार का फैसला कोरोना वायरस के प्रसार से जुड़े आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

एक बयान जारी कर उपराष्ट्रपति ने लोगों से अपील की कि सरकार जो भी फैसला ले, उसका पालन करें और उसी भावना से सहयोग करें जो अभी तक दिखी है भले ही 14 अप्रैल के बाद भी कुछ कठिनाइयां बनी रहें। वेंकैया ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें लोगों के स्वास्थ्य को ही महत्व मिलेगा। अर्थव्यवस्था की चिंताओं को टाला जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं। वेंकैया ने कहा कि जब कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के प्रयास सफलता का संकेत दे रहे थे तभी तब्लीगी जमात का मामला सामने आ गया जिसने प्रतिबंधों की प्रकृति में बदलाव कर दिया क्योंकि संक्रमण के ज्यादातर नए मामले इसी जमावड़े से सामने आ रहे थे। इस जमावड़े में हिस्सा लेने वालों की संख्या और इसके कई गुना असर ने हमारी उम्मीदों को झटका दिया। इस प्रकरण ने उन परिणामों को रेखांकित किया जो शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने पर सामने आ सकते हैं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की अवधि इस समय भले ही अनिश्चित हो, लेकिन आखिर में जीत हमारी ही होगी। उन्होंने कहा कि बुद्धिमानी इसी में है कि दुनियाभर में लोगों की सेहत और संपदा का कम से कम नुकसान हो। भारत ने यही भावना दिखाई है और इसे आखिर तक बरकरार रखने की जरूरत है। आइए बेहतर कल के लिए कुछ और समय कठिनाइयों के साथ जिएं।

सोनिया बोलीं, गैरजरूरी खर्च को तीस फीसद तक घटाए केंद्र सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कोरोना से लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिए पांच सुझाव
- कहा, केयर्स फंड की राशि पीएम राहत सहायता कोष में हो स्थानांतरित

सोनिया गांधी फाइल फोटो

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना से लड़ाई के लिए संसाधन जुटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गैरजरूरी सरकारी खर्चों में 30 फीसद कटौती की सलाह दी है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने पत्र में इन सुझावों का जिक्र किया है। मोदी से सोमवार को फोन पर हुई अपनी वार्ता का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने कहा है कि वे सकारात्मक भाव से पांच सुझाव दे रही हैं।

सोनिया ने कहा कि सांसदों के वेतन में 30 फीसद कटौती का वे समर्थन करती हैं। उन्होंने अति संयमित खर्च को समय की मांग बताते हुए 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे 'सेंट्रल विस्टा' ब्यूटीफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया। सोनिया ने वेतन, पेंशन एवं सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं को छोड़ केंद्र के अन्य खर्च में भी 30 फीसद की कटौती का सुझाव दिया है। उनके मुताबिक इस कटौती से सालाना करीब ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों तथा नौकरशाहों की सभी विदेश यात्राओं को भी फिलहाल स्थगित करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि आपातकालीन और अति आवश्यक विदेश यात्राओं की अनुमति पीएम की सहमति से ही होनी चाहिए।

'पीएम केयर्स' फंड की राशि को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' में स्थानांतरित करने का सुझाव देते हुए सोनिया ने कहा है कि यह ज्यादा प्रभावी होगा। पीएम राहत कोष में लगभग 3800 करोड़ रुपये की राशि बिना उपयोग के पड़ी है। पीएम-केयर्स की राशि को मिलाकर इसका उपयोग हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए किया जा सकता है। पांचवें सुझाव के तौर पर उन्होंने कोरोना और स्वास्थ्य चुनौतियों को छोड़कर टीवी, प्रिंट व ऑनलाइन सरकारी विज्ञापनों को दो साल तक रोकने की बात कही है।

सोशल मीडिया से भड़काऊ वीडियो और पोस्ट तुरंत हटाने के निर्देश

फरमान ▶ ऐसे पोस्ट से सरकार को कोरोना जंग के कमजोर होने की आशंका

कंपनियों को कार्रवाई के संबंध में रोजाना मंत्रालय को रिपोर्ट देने का निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोरोना वायरस को लेकर समुदाय विशेष को उकसाने वाले वीडियो की जांच रिपोर्ट के बाद सरकार ने इस प्रकार के वीडियो व अन्य पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि इन प्लेटफार्मों का इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ उसकी जंग को कमजोर करने में किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश में सोशल मीडिया से जुड़ी कंपनियों को भड़काऊ पोस्ट और वीडियो को हटाने के संबंध में रोजाना मंत्रालय को रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म में मुख्य रूप से टिकटॉक, हैलो व वाट्सएप शामिल हैं। मंत्रालय ने फेक न्यूज चलाने और उन्हें वायरल होने से रोकने के प्रयासों में सोशल मीडिया कंपनियों को आगे आकर काम करने को कहा है।

आइटी मंत्रालय इंटरनेट पर फर्जी खबरों का संज्ञान लेते हुए पहले ही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाली सामग्रियां हटाने के लिए कह चुका है।

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों के खिलाफ समुदाय विशेष को उकसाने के लिए टिकटॉक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर बड़े स्तर पर भड़काऊ वीडियो डाले जा रहे हैं। तथ्यों की जांच करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी वॉयेजर इंफोसेक की एक रिपोर्ट में इसे उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ये वीडियो भारत के साथ ही अन्य देशों में भी शूट किए जा रहे हैं। कंपनी ने यह रिपोर्ट भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को सौंप दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारियों तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी परामर्शों के खिलाफ धर्म की आड़ में भड़काऊ सामग्रियों को परोसने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया जा रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में 30 हजार से अधिक वीडियो का विश्लेषण किया गया है। इसके बाद पाया गया कि इनमें से अधिकांश वीडियो पेशेवर सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किए जा रहे हैं। जिन खातों से इन्हें सबसे पहले शेयर किया जा रहा है, उन्हें वीडियो के वायरल होते ही डिलीट किया जा रहा है।

वाट्सएप पर एक समय में एक ही मैसेज फारवर्ड होगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना के चलते सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफार्म वाट्सएप अब अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए एक समय में एक मैसेज एक ही व्यक्ति को भेजेगा। इससे पहले यह सुविधा एक साथ पांच लोगों को संदेश भेजने तक की थी।

वाट्सएप ने यह कदम भारत समेत विभिन्न देश सोशल मीडिया में कोविड-19 को लेकर बढ़ रही अफवाहों, फेक न्यूज और भ्रामक खबरों को प्रसारित होने से रोकने के लिए उठाया है। फेसबुक ने मंगलवार को एक बयान जारी करके कहा कि वह मानते हैं वाट्सएप को केवल दो लोगों की निजी बातचीत के जरिये तक सीमित रख के संदेशों के प्रसार की रफ्तार को कम करना अहम कदम साबित होगा। भारत में 40 करोड़ से अधिक यूजर वाली कंपनी का कहना है कि लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के समय में लोग वाट्सएप जैसे प्लेटफार्मों का बेहद उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में यह अहम कदम है। पिछले साल भी भारत सरकार की सख्ती के बाद एक साथ सभी को मैसेज फॉरवर्ड करने की सुविधा को सीमित करते हुए इसे अधिकतम पांच लोगों तक ही सीमित किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के संवेदनशील दौर में और सख्ती जरूरी है।

आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी न होने दें : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि देश में 21 दिन के लॉकडाउन के चलते आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी न होने पाए।

गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि आवश्यक वस्तुओं की गहन समीक्षा के बाद यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और प्रशासन से कहा गया है कि वह सामान की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए।

पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सरकार चिकित्सा संबंधी गतिविधियों पर नजदीक से नजर रख रही है। सोमवार तक नागरिक उड्डन मंत्रालय की ओर से संचालित लाइफलाइन उड़ान के जरिये कार्गो विमान (मालवाहक विमान) से 200 टन सामग्री पहुंचाई गई। इसी प्रकार रेलवे ने 8897 रैक्स और 4.57 लाख वैगन से लोडेड आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं।

उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते देश में कई त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में सरकार लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। विभिन्न धर्मों और समुदायों के नेताओं से अपील की गई है कि वह इस दौरान लॉकडाउन का पालन कराने में मदद करें और लोगों को समझाएं।

प्रवासी मजदूरों को आर्थिक मदद पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कोर्ट ने दी जा रही सुविधाओं पर दाखिल केंद्र की स्थिति रिपोर्ट याचिकाकर्ता को देने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को तत्काल आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग पर फिलहाल कोई भी आदेश देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह कोई विशेषज्ञ संस्था नहीं हैं। वे सरकार के निर्णय पर अपना निर्णय नहीं थोप सकते। फिलहाल दस-पंद्रह दिनों तक वे सरकार की कार्रवाई में दखल नहीं देंगे। कोर्ट ने इस बीच सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के बारे में उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली स्थिति रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को देने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 13 अप्रैल तक टाल दी।

ये टिप्पणियां मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, संजय किशन कौल और दीपक गुप्ता की पीठ ने पूर्व ब्यूरोक्रेट और समाजसेवी हर्ष मंदर की याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं। कोर्ट ने मामले पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की। याचिका में प्रवासी मजदूरों को तत्काल आर्थिक मदद और न्यूनतम वेतन मुहैया कराए जाने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार से मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जिसमें बताया गया कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले पर सरकार निगाह बनाए हुए है और गृहमंत्री निगरानी कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें सरकार द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट की कापी नहीं मिली है। पीठ ने कहा कि उन्हें भी आज ही स्थिति रिपोर्ट मिली है। प्रशांत भूषण ने कहा कि चार लाख प्रवासी मजदूर शेल्टर होम में रह रहे हैं। ऐसे में सामाजिक दूरी तो मजाक बन कर रह गई है। इन लोगों को पैसे दिये जाएं और अपने घर जाने दिया जाए क्योंकि ये सब दिल्ली के बाहर के नहीं हैं बल्कि शहर मे ही घरों में रहते है। मेहता ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ये सब अपने अंदाज से कह रहे हैं। पीठ ने पूछा कि जब उन लोगों को खाना मिल रहा है तो पैसे क्यों दिये जाएं। भूषण ने कहा कि उन्हें पैसे उनके घर भेजने के लिए दिये जाएं क्योंकि उनके घर भी उन्हीं पर निर्भर हैं। पीठ ने कहा कि जब आपने अभी तक सरकार की स्थिति रिपोर्ट नहीं देखी है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार कुछ नही कर रही। भूषण ने कहा कि सरकार ने मजदूरों को वेतन देने और किराया न लेने का जो आदेश दिया है वह व्यवहारिक नहीं है। पीठ ने कहा कि वे फिलहाल कोई आदेश नहीं दे सकते। वे इस क्षेत्र में एक्सपर्ट बाडी नहीं हैं। वे दस-पंद्रह दिन तक सरकार की कार्रवाई में दखल नहीं देंगे। पीठ ने भूषण से कहा कि वे सरकार की स्टेट्स रिपोर्ट लें और उसे देखें इसके बाद मामले पर 13 अप्रैल को फिर सुनवाई की जाएगी।

'बीमार कैदियों की रिहाई के लिए नहीं दे सकते आदेश'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोरोना के मद्देनजर जेलों में बंद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गुर्दे व सांस संबंधी बीमारियों से ग्रसित 50 साल से ऊपर के कैदियों की पैरोल व जमानत पर रिहाई के लिए केंद्र या राज्य सरकारों को कोई आदेश नहीं दे सकते।

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोवडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की खंडपीठ ने कहा कि हमें नहीं पता कि सरकार क्या सोच रही है लेकिन कोर्ट का मानना है कि एक-एक मामले को उसकी अहमियत से परखा जाये। हम इस मामले में कोई आदेश नहीं थोप सकते। हम याचिकाकर्ता एडवोकेट अमित साहनी को यह याचिका वापस लेने के साथ इस बात की अनुमति देते हैं कि वे बीमार कैदियों को संबंधित सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का परामर्श दें क्योंकि हम इस मामले में कोई आदेश देने को औचित्यपूर्ण नहीं मान रहे हैं।

ब्रिटेन में फंसे छात्रों को वापस लाने पर मांगा जवाब

नई दिल्ली : कोरोना के चलते ब्रिटेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की मांग पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका दिल्ली की रहने वाली मधुरिमा मृदुल ने दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को अर्जेंट मानते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के कारण चल रहे लॉकडाउन के कारण बहुत से छात्र ब्रिटेन में फंसे हैं। ब्रिटेन व जर्मनी ने भारत सरकार से कहा है कि वह छात्रों के स्वदेश लौटने में मदद करे। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, भविष्य में इसके लिए मुंबई और दिल्ली से फ्लाइट चलेगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि जो फ्लाइट ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन जा रही है, उसी में वहां फंसे उन भारतीय छात्रों को लाया जाए, जो यहां आना चाहते हैं। कोर्ट मामले में 13 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी।

देश में सालाना 20 करोड़ क्लोरोक्विन टैबलेट बनाने की क्षमता

राजीव कुमार, नई दिल्ली

- आवश्यकता पड़ने पर 50 फीसद तक बढ़ाई जा सकती सकती है उत्पादन क्षमता, देश को 10 करोड़ गोली के आपात स्टॉक की जरूरत
- फार्मा एक्सपोर्ट काउंसिल ने कहा, निर्यात के संबंध में मंत्रालय से नहीं मिला नोटिफिकेशन

कोरोना के इलाज के लिए देश में क्लोरोक्विन गोली की कोई कमी नहीं है और निर्यात होने की स्थिति में भी घरेलू स्तर पर इसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं आएगी। फार्मा इंडस्ट्री बॉडी इंडियन ड्रग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार मदान के मुताबिक हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन की टैबलेट बनाने के लिए जरूरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रिडिएंट्स (एपीआइ) की देश में सालाना उत्पादन क्षमता 40 टन की है। इससे सालाना 20 करोड़ हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन गोली बनाई जा सकती है। गत चार वर्षों के दौरान देश में हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन गोली की औसतन सालाना खपत 2.4 करोड़ रही है। यानी घरेलू जरूरत की पूर्ति के बाद 13 करोड़ अतिरिक्त गोली बनाने की क्षमता है। जरूरत पड़ने पर एपीआइ की 40 टन की क्षमता को 60 टन के स्तर तक लाया जा सकता है और अतिरिक्त 10 करोड़ गोली का उत्पादन किया जा सकता है।

फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन दिनेश दुआ ने बताया सरकार ने महामारी को देखते हुए 10 करोड़ हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन की गोली का आपात कोटा रखने को कहा है, जबकि हमारी क्षमता इससे काफी अधिक है। काउंसिल ने वाणिज्य मंत्रालय से कहा है कि चीन से हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन के कच्चे माल को एयरलिफ्ट करने की इजाजत मिल जाती है तो वे काफी कम समय में काफी अधिक संख्या में हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन बना सकते हैं। ऐसे में, हमारे पास घरेलू खपत के बाद भी निर्यात के लिए बड़ी संख्या में हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन की गोली उपलब्ध होगी।

हाल ही में कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन अमेरिका समेत दो दर्जन से अधिक देशों ने भारत से हाइड्रोक्सो लोरोक्विन देने की मांग की है। दवा निर्यात की फिर से इजाजत देने की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। दुआ कहते हैं, इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से न तो कोई अधिसूचना जारी की गई है और न ही निर्यातकों को जानकारी दी गई है। काउंसिल का कहना है कि हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन के निर्यात पर रोक से पूर्व ही कई देशों से ऑर्डर मिल चुके थे और उनको निर्यात पर रोक नहीं लगाई गई है।

ट्रंप ने दी थी कार्रवाई की धमकी

प्रथम पृष्ठ से आगे

भारत की तरफ से यह स्पष्टीकरण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के तुरंत बाद आया है जिसमें उन्होंने बदले की कार्रवाई करने की धमकी दी है। ट्रंप ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, 'सोमवार सुबह मेरी पीएम नरेंद्र मोदी से बात हुई थी जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आपूर्ति पर चर्चा हुई थी। भारत की जनसंख्या ज्यादा है और उन्हें अपना भी ख्याल रखना है लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह अमेरिका की मांग मानेंगे। भारत अमेरिका के साथ काफी अच्छा कारोबार करता है। भारत पहले भी अमेरिका के साथ कारोबार करके बहुत फायदा उठा चुका है। अगर भारत आपूर्ति नहीं करता है तो यह उसका फैसला होगा लेकिन ऐसा होने पर प्रतिशोध की कार्रवाई भी हो सकती है।'

सोमवार देर शाम 14 तरह की दवाओं पर रोक में ढील का निर्देश : डीजीएफटी ने सोमवार देर शाम को 14 तरह की दवाओं पर लगी रोक में ढील देने संबंधी निर्देश दे दिया है। वैसे एचएसक्यू और पैरासिटामॉल को अभी भी लाइसेंस वाली सूची में ही रखा गया है। लेकिन जरूरतमंद देशों को इसकी आपूर्ति की जाएगी। जिन कंपनियों ने निर्यात करने का आर्डर हासिल किया है, वे अब निर्यात कर सकेंगी। भारत ने स्पष्ट किया है कि पड़ोसी देशों को वरीयता के तौर पर एचसीक्यू व पीसीएम दिया जाएगा। वैसे सरकार ने कुल 24 दवाओं और उनके अवयवों को निर्यात की छूट दी है। इसमें तिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, एक्यीक्लोविर, विटामिन बी-1, बी-6 व बी-12, प्रोगेस्टरवन, क्लोरोमफेनिकोल, ओमिडाजोल और उनके अवयव भी शामिल हैं।

जीवन रक्षक दवाएं पहले भारतीयों को उपलब्ध कराई जाएं : राहुल गांधी

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत को सभी देशों की मदद करनी चाहिए लेकिन जीवन रक्षक दवाइयों को पहले भारतीयों को उपलब्ध कराना चाहिए। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि दोस्ती का मतलब बदला लेना नहीं है। जरूरत के समय में भारत को सभी देशों की मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले भारी तादाद में इन जीवन रक्षक दवाइयों को भारतीयों के लिए रखा जाए। ताजा घटनाक्रम पर कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट करके कहा है कि शर्तों के साथ की गई दोस्ती कोई दोस्ती नहीं है। भाजपा सरकार जो भी दूसरे देशों के लिए कर रही है, उसे उस पर विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले और सबसे ज्यादा अहमियत अपने नागरिकों को देनी चाहिए। पार्टी ने कहा कि यह पूरे देश के लिए शर्मनाक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार को धमकी दी है कि अगर दवाओं की आपूर्ति की अनुमति नहीं दी गई तो वह बदले की कार्रवाई करेगा। पीएम मोदी ने पूरा एक महीना और सौ करोड़ रुपये 'नमस्ते ट्रंप' पर बर्बाद कर दिए थे। और पूरी तरह से उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। और इसीलिए दवाओं के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है।

फैसला

आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई और डिब्बों को आइसोलशन वार्ड में तब्दील करने पर होगा खर्च, आने वाले समय में मिल सकती है और मदद

कोरोना फंड से रेलवे को फिलहाल मिलेंगे 950 करोड़

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक फोटो

कोरोना महामारी से संघर्ष में रेलवे के प्रशंसनीय प्रयासों को देखते हुए केंद्र सरकार ने रेलवे को कोविड-19 फंड से 950 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

यात्री यातायात में घाटे के बावजूद रेलवे इन दिनों कोरोना संकट से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 950 करोड़ रुपये की इस रकम का उपयोग आवश्यक वस्तुओं को देश के विभिन्न भागों में निशुल्क पहुंचाने और यात्री डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने पर आए खर्च की भरपाई में किया जाएगा। आने वाले वक्त में आकलन के अनुसार सरकार से रेलवे को और मदद भी मिल सकती है।

रेल मंत्रालय के अनुसार, पिछले 11 दिनों में आवश्यक वस्तुओं को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने में रेलवे ने तकरीबन 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जबकि कम से कम इतना ही और खर्च 14 अप्रैल तक करना होगा। यदि लॉकडाउन की अवधि बढ़ी तो ये खर्च इसी अनुपात में बढ़ जाएगा।

इसी प्रकार 5,000 यात्री डिब्बों में 80 हजार आइसोलेशन बेड तैयार करने में भी तकरीबन इतनी ही राशि खर्च होगी। अभी तक रेलवे 2,500 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर 40 हजार बेड का इंतजाम कर चुकी है। जबकि 14 अप्रैल तक पूरे 5,000 कोच आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिए जाएंगे। एक कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने पर करीब दो लाख रुपये का खर्च आता है। जबकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हर डिब्बे को फिर सामान्य स्थिति में लाने में एक लाख रुपये का और खर्च आएगा। इस तरह इस प्रक्रिया में रेलवे को कुल 150 करोड़ रुपये का खर्च वहन करना होगा। यदि और डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने की नौबत आई तो खर्च इसी अनुपात में बढ़ेगा। इसके लिए रेलवे ने 20 हजार यात्री डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने की तैयारी कर रखी है।

इसके अलावा रेलवे की कई इकाइयां और कार्यशालाएं कोरोना से बचाव का सामान भी बना रही हैं। जिनमें कवरऑल पीपीई सूट, वेंटीलेटर, मास्क और सैनेटाइजर शामिल हैं। बाकी रकम का उपयोग इनका कच्चा माल खरीदने में किया जाएगा।

रेलटेल की बदौलत चल रहा रेलवे का काम

लॉकडाउन की वजह से रेलवे का सारा प्रशासनिक कार्य मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल द्वारा उपलब्ध कराए गए दूरसंचार एवं ब्रॉडबैंड नेटवर्क की बदौलत डिजिटल और ऑनलाइन तरीकों से हो रहा है। रेलवे की सारी संचार प्रणाली, वीडियो कांफ्रेंसिंग और ई-ऑफिस प्लेटफार्म की व्यवस्थाएं रेलटेल ने ही तैयार की हैं, जिन्हें वह गुरुग्राम और सिकंदराबाद स्थित अपने दो डेटा केंद्रों से संभालती है। मौजूदा संकट की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं की मालगाड़ियों के जरिये ढुलाई भी फ्रेट ऑपरेशंस एंड इंफॉरमेशन सिस्टम के जरिये रेलटेल के नेटवर्क पर ही संचालित हो रही है। खास बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान रेलटेल का सारा कामकाज मात्र दो-तीन नियमित कर्मचारियों के माध्यम से रोटेशन के आधार पर हो रहा है जिनके रहने और खाने-पीने के इंतजाम रेलटेल के करीबी आवासीय परिसर में ही किए गए हैं। रेलटेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने कहा कि चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद हमारी टीम चौबीसों घंटे काम कर रही है और किसी भी फॉल्ट को ठीक करके नेटवर्क को सुरक्षित रख रही है। यही वजह है कि प्रशासनिक और प्रचालनात्मक कामकाज के साथ रेलवे बोर्ड और जोनल महाप्रबंधकों के बीच होने वाला संचार और वीडियो कांफ्रेंसिंग भी निर्बाध रूप से हो रही है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी